दैनिक अथाह

गाजियाबाद, सोमवार
25 दिसंबर, 2023

नये साल के जश्न में रखें दिल का विशेष ख्याल

युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक के मद्देनजर चेतावनी

AN INITIATIVE OF
THAKUR
FOUNDATION

,बृजेश सिंह

नई दिल्ली। बदलती जीवनशैली व खानपान के चलते लोगों की सेहत के लोकर जहां तमाम समस्याएं पैदा हो रही हैं वहीं हार्ट संबंधी समस्यायें भी बढ़ी हैं लेकिन वर्ष 2019 में कोविड महामारी के बाद से यह देखने में आ रहा है कि कम उम्र के युवा जो बेहद सेहतमंद नजर आते हैं अचानक हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। ऐसे युवाओं को हार्ट अटैक आने पर कई बार आभास भी नहीं होता है तथा जब तक सही इलाज मिले उनकी मौत हो जा रही है। कुछ महीने पहले गुजरात में गरबा महोत्सव के मौके पर राज्य सरकार ने युवाओं के लिए चेतावनी जारी करने के साथ ही पूरे प्रदेश में डांडिया नृत्य वाले स्थानों पर इमरजेंसी मेडिकल टीम तथा एम्बुलेंस की भी तैनाती की थी। नृत्य के दौरान वहां कई युवाओं को हार्ट की समस्या की शिकायत मिली थी। यही नहीं एक युवक की हार्ट अटैक से मौत भी हो गई थी।

उच्च स्तरीय चिकित्सीय सलाह के चलते राजधानी दिल्ली सहित देश के सभी बड़े महानगरों में जहां नये साल का जश्न धूमधाम से मनाया जाता है एकबार फिर युवाओं को दिल का विशेष ख्याल रखने तथा सांस संबंधी किसी तरह की शिकायत होने पर चिकित्सक की राय लेने की सलाह जारी की गई है। युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक की प्रवृति को यद्यपि 2021 में नोटिस किया जाने लगा था लेकिन 2023 में इसकी संख्या काफी बढ़ गई है। कई सेलेब्रेटी भी कम उम्र में अचानक हार्ट अटैक का शिकार बन चुके हैं। मिस युनिवर्स रह चुकी सुष्मिता सेन को इसी साल फरवरी में हार्ट अटैक की खबर सामने आई थी। वे 47 साल की हैं। तेलगू एक्टर हरिकंठ (33 वर्ष) की एक जुलाई को हार्ट अटैक से मौत हो गई। टेलीविजन एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला (40वर्ष), दक्षिण भारतीय फिल्मों के एक्टर पुनेठ राजकुमार, एक्टरर चिरंजीवी सारजा जैसे अनेकों नाम हैं जो तीस से चालीस वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक का शिकार बन चुके हैं। दिल्ली में भी ऐसी कई घटनाएं घट चुकी हैं जब सुबह टहलते अथवा जिम में एक्सरसाइज करते हुए युवांओं की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। इन्हीं घटनाओं के मद्देनजर नये साल के जश्न में शराब पीने तथा डांस के दौरान युवाओं के दिल को खतरे का अंदेशा है। कम उम्र के चलते दिल संबंधी प्राब्लम को कई बार युवा अंदाज नहीं लगा पाते हैं तथा वे खुद को फिट मानकर सामान्य गतिविधियों में लगे रहते हैं।

गौतम बु

ज्ञान

दीक्षांत सम

- समारोह
अतिथि दे
उप राष्ट्र
धनखड़,
स्वागत
- देश, का
के हिसाब
रहती है
धर्म शाश

अथाह संवाददाता

गौतम बुद्ध
मुख्यमंत्री
आदित्यनाथ रविव
ग्रेटर नोएडा स्थित
बुद्ध विश्वविद्याल
दीक्षांत समारोह में
हुए। विश्वविद्या
कुलाधिपति के रू
योगी ने देश के उप
धनखड़ का दीक्ष
स्वागत एवं अभि
दौरान अपने उद्बोध
उप राष्ट्रपति द्वारा
बावजूद सड़क मार्ग
ही समारोह में पहुंच
लिए प्रेरणादायी बत
उप राष्ट्रपति को श
आदर्श प्रतिमूर्ति बत
कहा कि गौतम बुद्ध
बुद्धि और विवेक से
करते हुए टीम भाव

आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से केजरीवाल की छवि खराब किए जाने की शिकायत की थी, जिसके बाद अब ये कार्रवाई की गई है।आम आदमी पार्टी की ओर से

अधिनियम का उल्लंघन हुआ है। कहा कि इस उल्लंघन के संदर्भ में आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है।

नई दिल्ली से बुधवार को पर्थ में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास 'ऑस्ट्रेलिया-हिंद' में भाग लेने के लिये ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले भारतीय सशस्त्र बलों की टीम। एजेंसी

काली पिक्चर्स द्वारा किया गया
फिल्म एनिमल 1 दिसंबर को
ज होगी।

बनाएंगे करण

करण जौहर, कार्तिक आर्यन
क आर्यन अपना बर्थडे

र्मा प्रोडक्शन ने कहा,
म एक नई कहानी की
जिसे धर्मा प्रोडक्शंस और
गया है।कार्तिक आर्यन
में बन रही इस फिल्म का
फिल्म 15 अगस्त, 2025 को
गौरवशाली भारतीय
कभी न भूलने वाला चैप्टर
है। ये सब्जेक्ट मेरे दिल के
धरहाउस करण जौहर और
करने पर एक्साइटेड हूं।

दंत चिकित्सा क्षेत्र को नया रूप देगा नेशनल डेंटल कमीशन, देश में पंजीकृत हैं 2.89 लाख दंत चिकित्सक

दंत चिकित्सा एवं इलाज में सुधार को नया कानून

बृजेश सिंह (दैनिक भास्कर)

नई दिल्ली। दंत चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता व सामर्थ्य को बढ़ाने तथा सभी लोगों तक इसकी पहुंच बनाने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले सत्र में संसद में नेशनल डेंटल कमीशन बिल पेश किया है।

दंत चिकित्सा को मेडिकल चिकित्सा का मुख्य अंश नहीं माना जाता है। यहां तक कि हेल्थ बीमा करने वाली कंपनियां भी दांत संबंधी इलाज को कवर नहीं करती हैं, जबकि देश में दांत संबंधी बीमारियों को लेकर लोगों में सजगता बढ़ी है। ग्रामीण इलाकों में दंत चिकित्सा की सुविधा न के बराबर है। डेंटल

कालेजों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। देश में डेंटल शिक्षा को लेकर तमाम निजी कालेजों की स्थापना हो चुकी है, लेकिन उनमें शैक्षणिक समानता नहीं है।

देश में करीब 2.89 लाख पंजीकृत दंत चिकित्सक हैं। इनमें अधिकांश शहरी क्षेत्रों में हैं।

आयोग में होंगे एक अध्यक्ष, 32 सदस्य

आयोग में एक अध्यक्ष, आठ पूर्णकालिक सदस्य और 24 अंशकालिक सदस्य होंगे, जो सभी केंद्र सरकार द्वारा चुने जाएंगे। इसके अतिरिक्त, विधेयक में केंद्र सरकार द्वारा एक दंत चिकित्सा सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रस्ताव है। परिषद आयोग को सलाह देगी और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगी।

सरकार की योजना है कि ग्रामीण स्तर पर सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कम से कम एक दंत चिकित्सक हो। केंद्र की ओर से ऐसा प्रस्ताव राज्यों को भेजा भी गया है, लेकिन अभी तक किसी भी राज्य में यह लागू नहीं हो सका है। देश में डेंटल शिक्षा के लिए अभी भारतीय दंत चिकित्सा परिषद नाम की संस्था है। नए विधेयक में इसकी जगह राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग नामक नई नियामक और नीति निर्धारण संस्था के निर्माण का प्रस्ताव है। आयोग नए कानून के लागू हो जाने के बाद बीडीएस अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए एक सामान्य योग्यता परीक्षा भी आयोजित करेगा, जिसे नेशनल एग्जिट टेस्ट (डेंटल) कहा जाएगा।

प्रस्तावित कानून के तहत निजी दंत चिकित्सा संस्थानों में 50 प्रतिशत सीटों की फीस तथा एडमिशन भी आयोग सीधे नियंत्रित करेगा। डेंटल बिल, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 की तर्ज पर तैयार किया गया है। इसे मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया के स्थान पर लाया गया था। प्रस्तावित बिल के अनुसार राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग देश में दंत चिकित्सा के प्रैक्टिस को विनियमित करने, उच्च गुणवत्ता, हाई क्वॉलिटी डेंटल एजुकेशन प्रदान करने और उच्च गुणवत्ता वाली ओरल हेल्थकेयर तक पहुंच बढ़ाने के लिए काम करेगा।

कोरोना की चपेट में आए गंभीर मरीजों में बढ़ सकती है हार्ट अटैक की संभावना, अध्ययन का दिया हवाला

कोरोना चला गया, लेकिन अभी नहीं टला खतरा

- **अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह**

बृजेश सिंह (दैनिक भास्कर)

नई दिल्ली। कोरोना महामारी की चपेट में आने वाले लोग जो अब ठीक हो चुके हैं, उनके लिए यह चेतावनी भरी खबर हो सकती है कि कोरोना से मुक्त होने के बाद भी अभी खतरा टला नहीं है। गंभीर रूप से कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके लोगों में हार्ट अटैक की बहुत अधिक संभावना है। ऐसे लोगों को भारत सरकार ने अतिरिक्त सावधानी बरतने तथा किसी भी तरह का भारी काम नहीं करे की सलाह दी है।

सख्त कसरत से परहेज आवश्यक

गंभीर रुप से कोविड से प्रभावित रहे व्यक्ति को सख़्त कसरत नहीं करनी चाहिए। कोविड की वजह से खून गाढ़ा हो जाता है, जिसके क्लॉट या थक्के बन जाते हैं। हार्ट अटैक कोलेस्टरॉल के जमने से नहीं होता। जिन्हें गंभीर कोरोना था और को-मॉर्बिडिटी है, उन्हें कोरोना से ठीक होने के कसरत या नृत्य आदि का धीरे-धीरे अभ्यास करना चाहिए। अगर मेहनत करने से आंखों के सामने अंधेरा छाना, चक्कर आना, सांस लेने में दिक़्क़त तथा छाती में दर्द जैसी शिकायतें हों तुरन्त डाक्टर से सलाह लेनी चाहिए।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के एक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके लोगों को भारी भरकम काम से बचना चाहिए। कोरोना के बाद होने वाले प्रभाव पर आईसीएमआर की द्वारा किए जा रहे इस शोध को अभी सार्वजनिक रूप से प्रकाशित नहीं किया गया है। आईसीएमआर में डॉ एना डोगरा ने बताया कि

आईसीएमआर ने अपनी अध्ययन रिपोर्ट पीयर रिव्यू यानी विशेषज्ञों को समीक्षा के लिए दे दी है। समीक्षा पूरी होने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय इसके बारे में जानकारी देगा। आईसीएमआर की रिपोर्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुई लेकिन इससे पहले कोरोना और शरीर पर होने वाले प्रभावों को लेकर दिल्ली स्थिति जीबी पंत अस्पताल में भी एक शोध किया गया था। साल 2020 से 2021 में 135 लोगों पर किए गए इस अध्ययन में ये पाया गया कि कोरोना वायरस का दिल पर इसका असर हुआ है।

शोध में शामिल किए गए लोगों को लगातार निगरानी में रखा गया और देखा गया कि कोरोना का असर समय के साथ दिल पर से कम होता गया। शोध में शामिल एक डॉक्टर बताया कि हमारे शोध में कोरोना से दिल पर असर होने की बात सामने आई है। कोविड वायरल प्रभावित व्यक्ति के हार्ट के इलैक्ट्रिकल सिस्टम, हार्ट की पंपिग मसल और हार्ट की धमनियों पर असर डालता है।

पूर्वांचल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगाया जापानी बुखार

अथाह संवाददाता

सबसे अधिक बच्चों की मौत इसी सिंड्रोम के कारण हुई

क्योंकि कई वर्षों तक इसकी चिकित्सा विशेषज्ञ पहचान ही नहीं कर पाए थे

गोरखपुर।

उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जिलों में पिछले चार दशक से भी अधिक समय से कम उम्र के बच्चों के लिए घातक महामारी के रूप में कुख्यात रहे जापानी बुखार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अथक प्रयासों से लगभग खत्म कर दिया गया है। मुझे अच्छी तरह याद है कि शुरूआत में इसे रहस्यमई बुखार कहा जाता था फिर कुछ डाक्टरों ने इसे जापानी बुखार (जापानी इंसेफेलाइटिस) बताना शुरू किया। अस्सी के दशक उत्तरार्ध में शुरू हुई इस बीमारी साल दर साल सैकड़ों बच्चे इलाज तथा रोग की पहचान न हो पाने के कारण मरते रहे हैं। तब से अभी तक

AN INITIATIVE OF
THAKUR
FOUNDATION

हर साल जुलाई से सितम्बर के बीच गोरखपुर व आसपास के जिलों में यह महामारी आती रही तथा बच्चों व उनके मां बाप के लिए कहर बनती रही। इन सालों में तमाम नेता व अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों दल इस क्षेत्र का दौरा करते रहे लेकिन इस बीमारी को प्रभावी ढंग से रोकथाम करने में सभी असफल रहे।

गोरखपुर में इंसेफेलाइटिस

	एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम		जापानी इंसेफेलाइटिस	
वर्ष	कुल मामले	मौतें	कुल मामले	मौतें
2017	764	111	52	2
2018	400	38	35	2
2019	227	10	35	2
2020	214	11	13	2
2021	228	15	12	0
2022	85	3	11	0
2023	88	0	0	0

इस बीच विशेषज्ञों ने पाया कि जापानी बुखार से पीड़ित बच्चे तो इलाज मिलने के बाद जीवित बच भी जाते थे लेकिन बच्चों के लिए हर साल काल बनने वाली बीमारी एक्यूट इन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम ;एईएसद्ध। इसके लक्षण भी जापानी इंसेफेलाइटिस की ही तरह होते हैं जिनमें तेज बुखार तथा दौरे पड़ते हैं। लेकिन इसके संक्रमण का कारण अज्ञात था। सबसे अधिक बच्चों की मौत इसी सिंड्रोम के कारण हुई क्योंकि कई वर्षों तक इसकी चिकित्सा विशेषज्ञ पहचान ही नहीं कर पाए थे। डाक्टरों ने सबसे पहला काम यह किया कि तेज बुखार लक्षण वाली बीमारियों की अलग अलग पहचान की जिसमें डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, स्क्रब टाइफस और लेप्टोस्पायरोसिस जैसी बीमारियों को एईएस सिंड्रोम से अलग किया गया। पिछले छह साल के प्रयास के बाद पहली बार एक्यूट इंसेफेलाइटिस से गोरखपुर में पीक सीजन बीत जाने के बाद एक भी मौत नहीं होने की रिपोर्ट आई है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिछले छह साल के प्रयासों को श्रेय दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जोकि गोरखपुर से निर्वाचित होते हैं ने स्वास्थ्य व चिकित्सा से जुड़े सभी विभागों को यहां मिलकर काम करने के लिए मजबूर किया। इससे पूरे इलाके में पीने शुद्ध पानी, सफाई, रोगों की जांच के लिए बेहतर लेबोरेटरीए अस्पतालों व प्राथमिक चिकित्सालयों में पर्याप्त मेडिकल स्टाफ का इंतजामए गोरखपुर में बच्चों में इंसेफेलाइटिस के इलाज के लिए 500 बेड का एक विशेष अस्पताल जैसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाये। यह नहीं इस रोग के रोकथाम के लिए लगातार उच्च स्तर से निगरानी भी की जाती रही है।

सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) के कारण होने वाली मौतें भी शून्य हो गई हैं। जहां 2017 में एईएस क 764 मामले मिले थे वहीं इस साल 2023 में यह संख्या घटकर 88 रह गई। इस साल एईएस से एक भी मौत नहीं होने की रिपोर्ट है।

मीडिया में आई कुछ रिपोर्ट के अनुसार निजी अस्पतालों में आने वाले इंसेफलाइटिस के कई मामलों को सरकारी रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। बावजूद इसके इस बीमारी से लगभग 45 सा ल के बाद गोरखपुर जिले में एक भी मौत नहीं होने की खबर राहत देने वाली है।

यद्यपि बाबा राघवदास मेडिकल कालेज स्थित इंसेफेलाइटिस के विशेष अस्पताल के रिकार्ड में इस साल इंसेफेलाइटिस से 11 मौतें दर्ज की गई हैं। इसके बारे में अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी एके चौधरी ने कि ये मौतें उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों तथा बिहार से इलाज के लिए आए मरीजों की थीं। गोरखपुर की तर्ज पर आसपास के जिलों में भी इंसेफेलाइटिस की रोकथाम के लिए गंभीर प्रयास किए जाने की जरूरत है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीन अक्टूबर को एक बयान में कहा था कि जेई और एईएस को जल्द ही राज्य से खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, राज्य सरकार 2017 से डेंगू, मलेरिया, एन्सेफलाइटिस, कालाजा और चिकनगुनिया जैसी संक्रामक बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए विशेष अभियान चला रही है: इन अभियानों से पिछले छह वर्षों में अच्छे परिणाम मिले हैं।

वर्षः 36, अंकः 319 गाजियाबाद,
मंगलवार 28 नवंबर 2023
पृष्ठः 6, मूल्यः 2 रुपए
Email: athahmedia@gmail.com,
Website : www.dainikathah.com

गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, अमरोहा, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर व हापुड़ में सर्वाधिक प्रसारित

दैनिक अथाह

समाचार • विचार • विश्लेषण

प्रादेशिक

पीएम-एबीएचआईएम व 15वें फाइनेंस कमीशन से जुड़ी योजनाओं के संचालन व पूर्ति... Page @ 5

चीन में फैली रहस्यमय बीमारी से भारत पूरी तरह... Page @ 4

गाजियाबाद

गुरू नानक देव जी के बताए मार्ग पर चलकर ही मानवता का... Page @ 3

दिल्ली का दम घोंट रहा है प्रदूषण

मिली सिर्फ नाकामी: ज्यों ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता ही गया

AN INITIATIVE OF
THAKUR
FOUNDATION

बढ़ता खतरा

- **अब यूपीएससी की परीक्षा में भी दिल्ली के प्रदूषण पर पूछे जाते हैं सवाल**

बृजेश सिंह

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली को अब दुनिया के बड़े शहरों में सबसे प्रदूषित शहर माना जाने लगा है। यह तब है कि जब दिल्ली देश का प्रमुख औद्योगिक शहर भी नहीं है। दिल्ली में प्रदूषण वाहनोंए कंस्ट्रक्शन तथा आसपास के राज्यों में पराली जलाने से हो रहा है। दिल्ली व एनसीआर का इन दिनों वायु प्रदूषण के चलते दम घुट रहा है। हवा में धुंआ व धूल के कणों की मात्रा खतरनाक स्थिति में लंबे समय से बनी हुई है। इससे लोगों को गंभीर बीमारियां हो रही हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में वायु प्रदूषण के चलते लगभग 22 लाख लोग फेफड़े की बीमारी व संक्रमण से ग्रसित हो चुके हैं इनमें से पचास फीसद बच्चे हैं। 25 नवम्बर 2019 में एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट जज अरुण मिश्रा ने टिप्पणी की थी कि प्रदूषण के चलते दिल्ली नर्क से भी बदतर बन चुकी है। उन्होंने कहा कि इससे ;प्रदूषणद्ध बेहतर होगा कि यहां बम गिराकर सभी को मार दीजिए। इससे केंद्रीय पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली में होने वाले वायु प्रदुषण में 41 फीसद योगदान मोटरगाडियों का है। वहीं 21ण्5 फीसद धूल तथा 18 फीसद पाल्यूशन फैक्ट्रियों के कारण होता है। कहा जा रहा है कि आटोमोबाइल इंडस्ट्री की मजबूत लाबी ने इस रिपोर्ट को सरकारी स्तर पर भी दबवा दिया। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण अब ऐसा विषय बन चुका है कि यूपीएससी की भर्ती परीक्षा में भी इसको लेकर सवाल पूछे जाने लगे हैं।

पिछले एक दशक पर नजर डालें तो राज्य व केंद्र की ओर से कई कोशिशें हुईं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। जाड़ों में यह जानलेवा बन जाता है।

प्रदूषण रोकने की दिशा में हुए प्रयासः

अक्टूबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक सदस्यीय जस्टिस लोकुर कमेटी का गठन कर पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने पर रोक लगाने की कोशिशों पर निगरानी का आदेश दिया।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने ग्रैप ;ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लानद्ध घोषित किया। प्रदूषण खतरनाक स्थिति में होने पर इसे लागू किया जाता है।

कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलीशन वेस्ट मैनेजमेंट के नियम बनाए गये।

रेड लाइट आनए गाड़ी आफ.कैम्पेन चलाया गया।

आड.इवेन रूल्स को दिल्ली में लागू किया गया।

ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने व पुराने पेड़ों की रक्षा का अभियान

एंटी स्माग गन का प्रयोग अति प्रदूषित इलाकों में किया गया।

पराली जलाने पर रोक के आदेश के साथ ही सब्सिडी की योजना

दिल्ली में मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम (एमआरटीएस) के तहत भारत.6 वाहनों को मंजूरी तथा इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दिया जा रहा है।

हालात के दबाव में सरकार ने फैसले तो कई लिए लेकिन इनको गंभीरता से लागू करने की कोशिश नहीं की गई। दिल्ली प्रदेश व केंद्र सरकार के बीच तालमेल की कमी तथा पराली के मामले में पड़ोसी राज्य हरियाणाए पंजाब तथा उत्तर प्रदेश से अपेक्षित सहयोग न मिलना भी इसका एक प्रमुख कारण है।

भुगतना होगा खामियाजा

दिल्ली एनसीआर में खतरनाक वायु प्रदूषण के चलते श्वसन संबंधी बीमारियों के साथ ही कई अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं अब देखने को मिल रही हैं। जिनका प्रभाव दूरगामी होगा। राजधानी की हवा में कार्बन मोनोआक्साइडए नाइट्रोजन आक्साइडए सल्फर आक्साइड तथा अन्य खतरनाक तत्व मौजूद हैं।

इनका हमारे शरीर पर कई तरह से प्रभाव पड़ रहा है। कुछ प्रभाव अभी दिखाई दे रहे हैं तथा कुछ प्रभाव लंबे समय बाद देखने को मिलेंगे। इसका बच्चों पर दीर्घकालिक असर देखने को मिलेगा क्योंकि यह उनके फेफड़े विकास के स्वाभाविक क्रम को प्रभावित कर सकता है। इससे उन्हें अस्थमा जैसी बीमारी का गंभीर खतरा है। दिल्ली के तमाम अस्पतालों में इस तरह के मरीजों बढ़ने की भी खबरें लेकिन सरकारी तौर पर अभी इसका आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया गया है। यह आज की तारीख में लंग कैंसर का एक प्रमुख कारण बन चुका है। इससे हृदय संबंधी बीमारियों के गंभीर होने की भी शिकायत मिल रही है। बड़ेए बच्चों व बूढ़े सभी में प्रदूषण के चलते इम्युनिटी ;रोग प्रतिरोधक क्षमताद्ध घट रही है। रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी से अन्य बीमारियों के अलावा घातक निमोनिया होने के मामले में अस्पतालों में आने लगे हैं।

दैनिक अथाह

गाजियाबाद, मंगलवार
19 दिसंबर, 2023

कालाजार: मरीजों की संख्या में गिरावट लेकिन रोग का उन्मूलन कब तक?

AN INITIATIVE OF
THAKUR
FOUNDATION

आंकड़े

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2002) में वर्ष 2010 तक कालाजार उन्मूलन की परिकल्पना की गई थी

बृजेश सिंह

नई दिल्ली। देश से काला अजार की बीमारी का उन्मूलन वर्ष 2023 में होने का लक्ष्य रखा गया था इस मामले में आंकड़ों से पता चलता है कि हम इस बीमारी के खात्मे के करीब हैं। काला अजार जिसे काला जार, काला बुखार तथा दम दम ज्वर के नाम से भी जाना जाता है। इस बीमारी का वैज्ञानिक नाम लीशमनियासिस है। भारत में पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दशक से इसका काफी प्रकोप रहा है। रेत मक्खी के काटने से फैलने वाली यह बीमारी पूरी तरह स्वदेशी है तथा भारत के साथ ही इसका प्रकोप बंगलादेश तथा नेपाल में भी देखने को मिलता है। विश्वस्वास्थ्य संगठन की मदद से बंगलादेश इस बीमारी से पूरी तरह मुक्त होने की घोषणा कर चुका है लेकिन भारत में यह अभी भी बरकरार है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2002) में वर्ष 2010 तक कालाजार उन्मूलन की परिकल्पना की गई थी। बाद में इस लक्ष्य की समय सीमा वर्ष 2015 तक बढा दी गई थी। वर्तमान में वर्ष 2023 तक कालाजार उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पिछले चार पांच सालों में कालाजार के मरीजों के संख्या तेजी से घटी है लेकिन अभी भी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश में छिटपुट मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मुख्यतया ग्रामीण इलाकों में फैलने वाली यह बीमारी मरीजों के संपर्क में रहने वाले लोगों को भी संक्रमित करती है।

देश अलग अलग राज्यों से वर्ष 2023 में कालाजार के कुल 530 मामले सरकारी तौर पर रिपोर्ट हुए हैं तथा इनसे कुल चार लोगों की मौत हुई है। इसके अतिरिक्त पोस्ट-कालाजार (डर्मल लीशमैनियासिस) के भी 286 मामले भी रिपोर्ट हुए हैं। ग्रामीण इलाकों में फैलने वाली इस बीमारी के सैकड़ों मामले में सरकारी रिपोर्ट में शामिल ही नहीं हो पाते हैं। फिर भी पिछले वर्षों की तुलना में यह आंकड़ा काफी कम है। सबसे मुख्य बात है कि इस बीमारी का न काला अजार क्या है?

विसेरल लीशमैनियासिस या काला अजार एक धीमी गति से बढ़ने वाली स्वदेशी बीमारी है। रेत मक्खी (सैंडफ्लाई) भारत में कालाजार के संक्रमण का एकमात्र स्रोत है। इसमें बुखार, वजन में कमी, प्लीहा और यकृत का बढ़ना आदि लक्षण देखे जाते हैं। यदि इसका उपचार न किया जाए तो 95 फीसद मामलों में यह घातक हो सकता है।

कालाजार के प्राथमिक उपचार में लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन ड इंजेक्शन दिया जाता है। ग्रामीण इलाकों में रेत मक्खी अक्सर कच्चे घरों की दीवार में अपना घर बना लेती हैं। आशा हेल्थ वर्कर के माध्यम से जागरूकता फैलाकर झारखंड, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में इसके उन्मूलन के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। उल्लेखनीय है पिछले साल जनवरी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में भारत से कालाजार बीमारी के 2023 में उन्मूलन किए जाने की बात कही थी। देखने है क्या अगले साल डब्ल्यूएचओ कालाजार के भारत उन्मूलन का सर्टीफिकेट दे सकेगा या अभी कुछ और साल इस बीमीरी को पूरी तरह खत्म करने में लगेंगे।